

एम/एस. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

बनाम

कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, रायपुर

(सिविल अपील संख्या 2150/2012)

07 दिसंबर, 2015

[ए. के. सिकरी और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा 11 एबी-शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज-बिक्री अनुबंध में मूल्य भिन्नता खंड के आधार पर मूल्य वृद्धि के कारण विक्रेता द्वारा उठाए गए पूरक चालान-ऐसे पूरक चालान के मूल्य पर विक्रेता द्वारा भुगतान किया गया विभेदक शुल्क-उक्त विभेदक शुल्क पर धारा 11 एबी के तहत ब्याज का भुगतान-आयोजित: जिस तारीख तक माल को मंजूरी दी गई थी, उस तारीख तक कीमत में वृद्धि होने की कोई निश्चितता नहीं थी-भविष्य में बाद की तारीख में हुई मूल्य वृद्धि के आधार पर माल की निकासी के समय निर्धारिती से उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद करना असंभव है-इस प्रकार, जब उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था, तो मंजूरी की तारीख को इसे 'अल्प भुगतान' नहीं माना जा सकता था। इस प्रकार, जब उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था, तो इसे उक्त तिथि पर 'अल्प भुगतान' के रूप में नहीं माना जा सकता था-इसके परिणामस्वरूप जब मूल राशि, अर्थात्

उत्पाद शुल्क स्वयं माल की निकासी की तारीख को (अंतर पर) देय नहीं था, तो ब्याज का भुगतान करने के लिए कानून का कोई सवाल नहीं हो सकता है-हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने पहले के फैसलों-एसकेएफ और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो मामले में कहा था कि पूरक चालान पर भुगतान किए गए शुल्क पर ब्याज देय होगा-उक्त पीठ ने धारा 11 एबी में होने वाले 'भुगतान किया जाना चाहिए' अभिव्यक्ति के प्रभाव पर विचार नहीं किया- इस प्रकार, एसकेएफ और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो मामले में निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है-मामले को वृहद पीठ को भेजा गया है।

मामले को वृहद पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने कहा:-

1.1.निर्धारिती ने इन वस्तुओं के मूल्य को दर्शाते हुए उठाए गए चालान के आधार पर और इन वस्तुओं की निकासी की तारीख तक अपने द्वारा स्वीकृत वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का निर्वहन किया था। "उक्त चालान में घोषित मूल्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के संदर्भ में माल का लेन-देन मूल्य था क्योंकि यह उन पक्षों के बीच निर्धारित मूल्य था जिन पर माल को हटाने के समय और स्थान पर आपूर्ति की जानी थी। विभेदक शुल्क का अवसर बाद की तारीख में बिक्री के अनुबंध में मूल्य भिन्नता खंड के कारण उत्पन्न हुआ। जिस क्षण निर्धारिती को मूल्य वृद्धि के कारण बढ़ी हुई कीमत प्राप्त हुई, उसने उक्त कीमत प्राप्त होने पर तुरंत अंतर शुल्क का भुगतान कर दिया। [पैरा 7)

(946-एफ-एच]

1.2 धारा 11एबी के तहत ब्याज लगाया/लिया जा सकता है जहां उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति में, ब्याज का भुगतान उस महीने की पहली तारीख से किया जाना चाहिए जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था। अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) में प्रावधान है कि माल का मूल्य माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य होगा। इसका अर्थ है वह मूल्य जो माल के खरीदार द्वारा 'भुगतान' या 'भुगतान करने के लिए सहमत' किया गया है। धारा 11एबी के प्रयोजनों के लिए, 'भुगतान किया जाना चाहिए' अभिव्यक्ति का अर्थ वह समय होगा जब विक्रेता और खरीदार द्वारा मूल्य पर सहमति हो। दूसरे शब्दों में, संशोधित मूल्य प्राप्त करने का विक्रेता का अधिकार केवल तभी स्पष्ट होता है जब खरीदार उसी प्रतिबंध के लिए सहमत होता है, और केवल उसी समय संशोधित मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने का दायित्व हो सकता है। दोनों पक्षों को उस समय अंतिम मूल्य के बारे में पता नहीं होता है जब माल हटाया जाता है। मंजूरी के बाद मूल्य संशोधन के संदर्भ में, खरीदार द्वारा संशोधित मूल्य की मंजूरी के बाद ही शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। मूल्य संशोधन के कारण अंतर शुल्क का भुगतान उस महीने में किया जाता है जब विक्रेता (निर्धारिती) और खरीदार के बीच संशोधित मूल्य पर सहमति होती है और इसका भुगतान केवल उसी समय किया जाना चाहिए था न कि पहले। [पैरा 19) [958-सी-एच]

1.3 'भुगतान किए जाने वाले शुल्क की मात्रा क्या होनी चाहिए' और 'जब ऐसा शुल्क देय हो' के बीच के अंतर को भी ध्यान में रखना होगा। मूल्य संशोधन के मामलों में, शुल्क की मात्रा बढ़ी हुई कीमत पर होगी, लेकिन अंतर शुल्क के भुगतान का समय तब होता है जब पक्ष कीमतों में वृद्धि के लिए सहमत होते हैं। उस सी गणना पर, यह होगा कि अंतर शुल्क के लिए ब्याज घड़ी अंतर शुल्क देय होने की तारीख से टिक करना शुरू कर देगी, यानी बढ़ी हुई कीमतों के समझौते की तारीख और उससे पहले नहीं। इस अवधारणा को ब्याज के भुगतान के लिए 'प्रासंगिक तिथि' के संबंध में 2015 में धारा 11ए में नवीनतम संशोधन के साथ स्पष्ट किया गया था। [पैरा 20) [959-ए-सी]

1.4 एस. के. एफ. मामले और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो मामले में पीठ, जिसने यह अभिनिर्धारित किया था कि ब्याज देय होगा, ने अधिनियम की धारा 11ए. बी. में आने वाली 'भुगतान किया जाना चाहिए था' अभिव्यक्ति के प्रभाव पर विचार नहीं किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिनियम की धारा 4 के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान 'लेनदेन मूल्य' पर किया जाना है और इस तरह के लेनदेन मूल्य को माल की निकासी के समय देखा जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से, जब माल को मंजूरी दी गई थी, तो उत्पाद शुल्क का भुगतान उस कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया था जो वास्तव में ली गई थी और उक्त उद्देश्य के लिए उठाए गए चालान में दिखाई दी थी। विभाग यह दलील नहीं दे सकता

कि उस तारीख तक यह कीमत नहीं ली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अंतर भुगतान बाद की तारीख में किया जाता है, तो मूल्य में उक्त अंतर के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क के लिए आगे की राशि देय हो जाती है। इसके अलावा, ऐसी घटना बाद की तारीख में हुई। जिस तारीख को माल को मंजूरी दी गई थी, उस तारीख तक इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि कीमतों में वृद्धि होगी और इस तरह की वृद्धि की सटीकता का पता लगाना समझ से परे था। भविष्य में मूल्य वृद्धि के आधार पर, माल की निकासी के समय, निर्धारित से उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद करना असंभव होगा। इसलिए, जब उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था, तो मंजूरी की तारीख को इसे उक्त तारीख को 'अल्प भुगतान' के रूप में नहीं माना जा सकता था। परिणामस्वरूप जब मूल राशि, अर्थात् उत्पाद शुल्क स्वयं माल की निकासी की तारीख को देय (अर्थात् अंतर पर) नहीं था, तो ब्याज का भुगतान करने के लिए कानून का कोई सवाल नहीं हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर मूल्य की प्राप्ति पर, जब खरीदार मूल्य में वृद्धि के लिए सहमत हो जाता है, तो आगे उत्पाद शुल्क भी देय हो जाता है और उस गणना पर यह कहा जा सकता है कि मूल रूप से भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क 'अल्प भुगतान' हो गया। हालांकि, यह केवल अंतर उत्पाद शुल्क पर भुगतान को आकर्षित करेगा, न कि उस पर ब्याज। [पैरा 21-22) [960-A-C]

1.5 एस. के. एफ. इंडिया लिमिटेड और इंटरनेशनल ऑटो में दो निर्णय एक ही पीठ द्वारा दिए गए हैं। इंटरनेशनल ऑटो एसकेएफ इंडिया लिमिटेड का अनुसरण करता है। पीठ जिस प्राथमिक कारक से प्रभावित थी, वह यह था कि सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और इसलिए सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। यह इस आधार पर आगे बढ़ता है कि मूल रूप से माल को हटाने के समय जो कीमत बताई गई थी, वह 'कम बताई गई' (इंटरनेशनल ऑटो) थी। हालांकि, शुल्क के उद्देश्य से माल का मूल्य 'हटाने के समय' है, जो मूल रूप से 1944 में अधिनियमित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की शुरुआत से मौलिक सिद्धांत बना हुआ है और आज तक वैध है। इसलिए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि उन वस्तुओं को हटाने की तारीख को कीमत 'कम' की गई थी। [पैरा 23] [960-डी-एफ]

1.6 पीठ की यह टिप्पणी कि ब्याज लगाना राजस्व के नुकसान के लिए विभाग को क्षतिपूर्ति करने के लिए है, जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के मामले में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है कि ब्याज प्रतिपूरक प्रकृति का था, विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था। संविधान पीठ ने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोटा और अन्य के मामले में पहले के तीन सदस्यीय पीठ के फैसले की शुद्धता पर विस्तार से विचार किया, जिसमें बहुमत का विचार था कि अवैतनिक कर बकाया पर दावा किया गया ब्याज

लिया जा सकता है क्योंकि यह चरित्र में प्रतिपूरक था न कि दंडात्मक।  
[पैरा 25] [962-डी-एफ]

1.7 एस. के. एफ. और ऑटो इंटरनेशनल में निर्णय के लिए दिए गए कारणों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह तत्काल मामले में शामिल मुद्दे पर गौर करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन करने के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे। [पैरा 27] [962-ए-बी]

\*सी. सी. ई. बनाम एस. के. एफ. इंडिया लिमिटेड (2009) 13  
सेकंड 461:2009 (10) एस. सी. आर. 714;

\* \* सी. सी. ई. बनाम इंटरनेशनल ऑटो लिमिटेड (2010) 2 एस.  
ई. सी. 672:10 (1) एस. सी. आर. 211; सी. सी. ई. बनाम रूचा  
इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड। पहली अपील सं. 2007 का 42 03.04.2007;  
एम. आर. = लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मद्रास (1997)  
5 पर निर्णय लिया गया। एस. सी. सी. 104;

\* \* \* जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी  
(1994) 4 एस. सी. सी. 276; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोटा और अन्य (1981) 4 एस. सी. सी.  
578:1982 (1) एस. सी. आर. 563; केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम  
आयकर आयुक्त, बॉम्बे (1965) 2 एस. सी. आर. 908-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2009 (10) एस. सी. आर. 714 का उल्लेख किया गया है	पैरा 11
2010 (1) एस. सी. आर. 211 निर्दिष्ट है	पैरा 11 ए
(1997) 5 धारा 104 निर्दिष्ट है	पैरा
24	
(1994) 4 धारा 276 निर्दिष्ट है	
पैरा25	
1982(1) एस.सी.आर.563 निर्दिष्ट	पैरा 25
(1965) 2 एस.सी.आर.908 निर्दिष्ट है	पैरा 26

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील संख्या 2150/2012

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अपील संख्या ई/367/2008 के साथ 2012 की सिविल अपील संख्या 2562 व 2013 की सिविल अपील संख्या 599,600 और 1522-1523 के निर्णय और आदेश संख्या 615/2010- Ex दिनांक 13.08.2010 से।

अपीलार्थी के लिए वी. लक्ष्मीकुमारन, एम. पी. देवनाथ, हेमंत बजाज, एल. चरणया, आदित्य भट्टाचार्य, आनंद के., टी. डी. सतीश।

प्रत्यर्थी की ओर से के. राधाकृष्णन, अरिजीत प्रसाद, ए. शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद।



न्यायालय का निर्णय निर्णय ए. के. सिकरी, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

1. इन सभी अपीलों में, कानून का समान प्रश्न शामिल है और संक्षिप्तता के लिए, हम 2012 की सिविल अपील No.2150 के तथ्यों पर ध्यान देकर कानून के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

2. अपीलार्थी/निर्धारिती, जो भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अपने द्वारा निर्मित लोहे और इस्पात के उत्पादों को भारतीय रेलवे को बेच रहा है। इस उद्देश्य के लिए, उक्त दोनों पक्षों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और भारतीय रेलवे को उनके बीच पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर माल बेचा जा रहा था। रेलवे को आपूर्ति के लिए इन वस्तुओं को हटाने पर, निर्धारिती माल को हटाने के समय जारी किए गए चालान में निर्धारिती द्वारा बताए गए मूल्य के अनुसार उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहा था। इस तरह से जनवरी, 2005 से जुलाई, 2006 की अवधि के दौरान वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी, जो तत्काल अपील में शामिल है। ऐसा हुआ कि अगस्त, 2006 में रेलवे द्वारा मूल्य में वृद्धि की गई थी। उस आधार पर, निर्धारिती को आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए बड़े हुए प्रतिफल के निर्धारण पर मूल्य अंतर का भुगतान किया गया था। निर्धारिती ने अगस्त, 2006 में स्वेच्छा से Rs.142.78 करोड़ के अंतर शुल्क का भुगतान किया। राजस्व/प्रत्यर्थी के अनुसार, चूंकि अंतर शुल्क का भुगतान अगस्त, 2006 में किया गया था

और माल की निकासी के समय भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अंतर शुल्क का भुगतान करने में देरी हुई और इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क-अधिनियम, 1944 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 एबी के तहत, निर्धारिती उसके द्वारा भुगतान की गई अंतर शुल्क राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। राजस्व के तर्क को सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) सहित नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा बरकरार रखा गया है।

3. इस प्रकार, इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या बिक्री अनुबंध में मूल्य भिन्नता खंड के आधार पर मूल्य वृद्धि के कारण पूरक चालान के तहत भुगतान की गई अंतर शुल्क राशि पर अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत ब्याज लगाया जा सकता है। अब, कुछ विस्तार से तथ्य: निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अध्याय 72 और 73 के तहत आने वाले लोहे और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ है। निर्मित अंतिम उत्पादों में रेल शामिल हैं। निर्धारिती द्वारा निर्मित अंतिम उत्पादों को उस पर देय उत्पाद शुल्क के उचित भुगतान पर मंजूरी दे दी जाती है। अंतिम उत्पादों को या तो सीधे कारखाने के द्वार पर बेचा जाता है या विभिन्न शाखा बिक्री कार्यालयों में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ से उन्हें ग्राहकों को बेचा जाता है। फैक्टरी या बीएसओ से बिक्री ग्राहकों से प्राप्त खरीद आदेशों के

संदर्भ में होती है। निर्धारिती ने मूल्य परिपत्र संख्या के संदर्भ में रेल को भारतीय रेलवे को बेच दिया। 2005 का एल. पी.-06 दिनांक 24.02.2005 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.2004 खरीद आदेशों में उद्धृत कीमतों की शर्तों के अनुसार, निर्धारिती ने रेल को हटाने के समय भारतीय रेलवे को केंद्रीय उत्पाद शुल्क का निर्वहन किया। इस तरह की कीमत दिए गए समय में अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में माल का "लेन-देन मूल्य" था। मूल्य भिन्नता खंड के संदर्भ में और भारतीय रेलवे के साथ समझौते के संदर्भ में, 01.07.2004 से प्रभावी 24.02.2005 दिनांकित मूल्य परिपत्र को सहमत मूल्य में वृद्धि के साथ ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। एक संशोधित मूल्य परिपत्र सं एल. पी.-010/06 दिनांकित 20.07.2006 को सहमत मूल्य को संशोधित करते हुए जारी किया गया था। संशोधित मूल्य परिपत्र के संदर्भ में निर्धारिती ने जनवरी, 2005 से जुलाई, 2006 की अवधि के दौरान साफ की गई रेल पर Rs.142,78,88,172/- के अंतर शुल्क का निर्वहन किया। विभागीय अधिकारियों को सूचित करते हुए अगस्त, 2006 में अंतर शुल्क का भुगतान किया गया था।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अगस्त, 2006 के महीने के लिए निर्धारिती द्वारा दायर ई. आर.-1 विवरणी की जांच पर, निर्धारिती को 01.06.2007 दिनांकित एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि Rs.142 के अंतर शुल्क के संबंध में। अगस्त, 2006 में 78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, निर्धारिती को

अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत Rs.15,51,81,231 का ब्याज देना आवश्यक है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि चूंकि माल को हटाने के समय कीमत सही ढंग से निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए शुल्क का कम भुगतान किया गया था, इसलिए निर्धारित ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि चूंकि कीमत अंतिम नहीं थी, इसलिए शुल्क को अस्थायी मूल्य पर भुगतान के रूप में माना जाना चाहिए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 7 (4) के संदर्भ में धारा 11 एबी के तहत ब्याज देय है। नोटिस ने यह आरोप लगाने के लिए 28.07.2003 दिनांकित परिपत्र पर भी भरोसा किया कि निर्धारित कीमत को ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। नोटिस में नियमों के नियम 7 और 8 के उल्लंघन के लिए नियम 25 के तहत जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है।

5. निर्धारित कीमत ने कारण दर्शाओ नोटिस में निहित आरोपों को चुनौती देते हुए दिनांक 17.10.2007 पर विस्तृत जवाब दायर किया और तर्क दिया कि मूल्य भिन्नता के कारण भुगतान किए गए अंतर शुल्क पर कोई ब्याज देय नहीं है।

6. केंद्रीय आयुक्त, रायपुर ने कारण दर्शाओ नोटिस में प्रस्तावित ब्याज की राशि की पुष्टि करते हुए दिनांक 31.10.2007 का आदेश पारित किया और रुपये 2,00,000-का जुर्माना भी लगाया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क

आयुक्त, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 31.10.2007 के आदेश के खिलाफ, निर्धारिती ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने दिनांकित 13.08.2010 का विवादित आदेश पारित किया है और अपील को खारिज कर दिया है। इस आदेश को तत्काल अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

7. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्धारिती ने इन वस्तुओं के मूल्य को दर्शाते हुए उठाए गए चालान के आधार पर और इन वस्तुओं की निकासी की तारीख तक अपने द्वारा स्वीकृत वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का निर्वहन किया था। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि उक्त चालान में घोषित मूल्य अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में माल का लेनदेन मूल्य था क्योंकि यह उन पक्षों के बीच निर्धारित मूल्य था जिन पर माल को हटाने के समय और स्थान पर आपूर्ति की जानी थी। विभेदक शुल्क का अवसर बाद की तारीख में बिक्री के अनुबंध में मूल्य भिन्नता खंड के कारण उत्पन्न हुआ। जिस क्षण निर्धारिती को मूल्य वृद्धि के कारण बढ़ी हुई कीमत प्राप्त हुई, उसने उक्त कीमत प्राप्त होने पर तुरंत अंतर शुल्क का भुगतान कर दिया।

8. इस पृष्ठभूमि में इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या रेलवे द्वारा बाद की तारीख को लिए गए निर्णय के अनुसार कीमत में अंतर को उस तारीख की कीमत के रूप में माना जा सकता है जब माल को वास्तव में हटा दिया गया था और इसलिए, यह अर्थ लगाया जाना

चाहिए कि इस घटना को अधिनियम की धारा 11 एबी के दायरे में लाने के लिए शुरू में भुगतान किया गया शुल्क 'कम भुगतान' था। निर्धारिती के अनुसार, अधिनियम की धारा 11 एबी के प्रावधानों को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह की कल्पना के बिना, यह माना जा सकता है कि माल को हटाने की तारीख को जब उस समय निर्धारित मूल्य के अनुसार शुल्क का भुगतान किया गया था, तो अब इसे 'अल्प-भुगतान' के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि बाद की तारीख में कोई घटना हुई थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी या इन वस्तुओं को हटाने के समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता था।

9. इस मामले की उचित समझ के लिए, हम इस स्तर पर अधिनियम की धारा 11 एबी के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

"(1) जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम कर दिया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है, वह व्यक्ति जो उप-धारा (2) के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, या जिसने धारा 11 ए की उप-धारा (28) के तहत शुल्क का भुगतान किया है, वह शुल्क के अलावा ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो अठारह प्रतिशत से कम नहीं है और प्रति वर्ष छत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना

द्वारा निर्धारित की जा रही है। बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां धारा 37 ख के तहत बोर्ड द्वारा आदेश, निर्देश या निर्देश जारी करने के परिणामस्वरूप शुल्क देय हो जाता है, और देय शुल्क की ऐसी राशि का स्वेच्छा से पूरा भुगतान किया जाता है, बिना किसी बाद के चरण में ऐसे भुगतान के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार सुरक्षित रखे, ऐसे आदेश, निर्देश या निर्देश जारी करने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, कोई ब्याज देय नहीं होगा और अन्य मामलों में ब्याज पूरी राशि पर देय होगा, जिसमें पहले से भुगतान की गई राशि भी शामिल है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां शुल्क देय हो गया था या उस तारीख से पहले भुगतान किया जाना चाहिए था जिस दिन वित्त विधेयक, 2001 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है।

स्पष्टीकरण 1.-जहां देय होने के लिए निर्धारित शुल्क आयुक्त (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, न्यायालय द्वारा कम किया जाता है, ब्याज शुल्क की ऐसी कम की गई राशि पर देय होगा।

स्पष्टीकरण 2.-जहां देय होने के लिए निर्धारित शुल्क को आयुक्त (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण या, यथास्थिति, न्यायालय द्वारा बढ़ाया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है, तो ब्याज शुल्क की ऐसी बढ़ी हुई या आगे बढ़ी हुई राशि पर देय होगा। उपरोक्त प्रावधान को केवल पढ़ने से पता चलता है कि इसे आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है:

(ए) शुल्क का गैर-लेवी या गैर-भुगतान.

(बी) शुल्क का छोटा शुल्क या छोटा भुगतान.

(सी) गलत धनवापसी.

(डी) धारा 11 ए (2) के तहत निर्धारित शुल्क।

10. इस मामले की उचित समझ के लिए, हम इस स्तर पर अधिनियम की धारा 11 एबी के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:

"(1) जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या अल्प-देय या अल्प-भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है, वह व्यक्ति जो उप-धारा (2) के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, या जिसने धारा 11 ए की उप-धारा (28) के तहत शुल्क का भुगतान किया है, वह शुल्क के अलावा, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो अठारह प्रतिशत से कम नहीं है और छत्तीस प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा महीने की पहली तारीख से निर्धारित किया जा रहा है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां शुल्क देय हो गया था या उस तारीख से पहले भुगतान किया जाना चाहिए था जिस दिन वित्त विधेयक, 2001 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है।



स्पष्टीकरण 1.-जहां देय होने के लिए निर्धारित शुल्क आयुक्त (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, न्यायालय द्वारा कम किया जाता है, ब्याज शुल्क की ऐसी कम की गई राशि पर देय होगा।

स्पष्टीकरण 2.-जहां देय होने के लिए निर्धारित शुल्क को आयुक्त (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण या, यथास्थिति, न्यायालय द्वारा बढ़ाया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है, तो ब्याज शुल्क की ऐसी बढ़ी हुई या आगे बढ़ी हुई राशि पर देय होगा। उपरोक्त प्रावधान को केवल पढ़ने से पता चलता है कि इसे आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है:

(ए) शुल्क का गैर-लेवी या गैर-भुगतान

(बी) शुल्क का कम शुल्क या कम भुगतान

(सी) गलत धनवापसी

(डी) धारा 11 ए (2) के तहत निर्धारित शुल्क

(ई) धारा 11 ए (2) के तहत धारा 11 ए के तहत जारी सूचना की आवश्यकता होती है।

(च) धारा 11 ए (2 बी) के तहत शुल्क भुगतान

(छ) आयुक्त (अपील) या अपीलीय न्यायाधिकरण आदि द्वारा देय होने के लिए निर्धारित किए गए ऐसे कम या बढ़े हुए शुल्क पर ब्याज देय है।

11. आगे बढ़ने से पहले, हम यह इंगित करना चाहेंगे कि हम एक वर्जिन क्षेत्र पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अधिनियम की धारा 11 एबी के प्रावधानों की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा लगभग समान परिस्थितियों में दो निर्णयों में पहले ही की जा चुकी है। ये हैं:

(ए) सी. सी. ई. बनाम एस. के. एफ. इंडिया लिमिटेड<sup>1</sup>

(बी) सी. सी. ई. बनाम इंटरनेशनल ऑटो लिमिटेड<sup>2</sup>

12. एस. के. एफ. इंडिया लिमिटेड के मामले में, निर्धारिती बॉल बेयरिंग और कपड़ा मशीन के पुर्जों के निर्माण और निर्माण में लगा हुआ था। इसने अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के भुगतान पर कुछ कीमतों पर बेचा, जो उस कीमत पर देय था जिस पर माल बेचा गया था। बाद में, पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कीमतों में संशोधन किया गया। संशोधन के बाद निर्धारिती ने अपने खरीदारों पर पूरक चालान जुटाए और पहले बेचे गए माल पर अंतर शुल्क का भी भुगतान किया। राजस्व ने यह विचार रखा कि निर्धारिती अंतर शुल्क पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह तथ्यात्मक स्थिति दर्शाती है कि यह लगभग वही थी जो वर्तमान अपीलों में प्रचलित है। हालांकि, ऑर्डर-इन-ओरिजिनल में की गई मांग को आयुक्त (अपील) द्वारा दरकिनार कर दिया गया था और आयुक्त जी (अपील) के आदेश को सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि जहां अंतर शुल्क के भुगतान और पहले बेचे गए सामानों के संबंध में कीमतों में वृद्धि के संशोधन के आधार पर

ग्राहकों को पूरक चालान जारी करने के बीच समय का अंतर था, वहां कोई ब्याज नहीं लिया जाता था।

न्यायाधिकरण के उक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा यह मानते हुए उलट दिया गया था कि अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत ब्याज देय था। धारा 11 एबी के प्रावधानों को दोहराने के बाद, न्यायालय ने पहली बार में बताया कि उपरोक्त प्रावधान को खुशी से नहीं कहा गया था और इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"9. यदि कानून का उद्देश्य उस व्यक्ति के दायित्वों को स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से बताना है जिसे कानून संबोधित करता है और कानून द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के परिणामों को स्पष्ट रूप से और बिना किसी भ्रम के स्पष्ट करना है, तो अधिनियम की चार धाराएं वांछित उद्देश्य से मीलों कम हैं। यहां तक कि मूल रूप से प्रावधानों को बहुत खुशी से तैयार और शब्दबद्ध नहीं किया गया था। समय-समय पर संशोधनों के अधीन वे प्रावधान अब इतने जटिल हो गए हैं कि उनके अर्थ को समझने के लिए उन्हें कई बार पढ़ना आवश्यक हो जाता है।

10. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि जिन दो अवधियों के लिए ब्याज लगाया जा सकता है, उन्हें धारा 11-एए और

11-एबी में विभाजित करने के बजाय एक समेकित प्रावधान में क्यों नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, धारा 11-ए के सभी विभिन्न उप-खंडों को पुनर्गठित करने और उस खंड की योजना को अधिक सुसंगत और पठनीय रूप में प्रस्तुत करने की बहुत गुंजाइश है। जो भी हो सकता है। हाथ में मामले में हमें कानून से निपटना होगा जैसा कि अभी है।"

13. इसके बाद, न्यायालय ने धारा 11 एबी और कुछ अन्य प्रावधानों के साथ धारा 11 ए के प्रावधानों की तुलना की। इसने सीसीई बनाम रुचा इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भी ध्यान दिया। 3 जिसमें बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 11 एबी ऐसी स्थिति में लागू नहीं होती है। हालाँकि, न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। हम उपरोक्त पहलू को छूते हुए प्रासंगिक चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, जैसा कि निर्णय में निहित है:

"11. धारा 11-ए गैर-लेवी या लघु शुल्क, गैर-भुगतान या अल्प-भुगतान या शुल्क की गलत वापसी के मामलों को दो श्रेणियों में रखती है। एक जिसमें शुल्क का गैर-भुगतान या अल्प-भुगतान, आदि छल के अलावा किसी अन्य कारण से होता है; डिफॉल्ट निरीक्षण या किसी गलती के कारण है और यह जानबूझकर नहीं है। दूसरा जिसमें शुल्क का गैर-

भुगतान या अल्प-भुगतान, आदि "धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने, या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन" के कारण है; इसका मतलब है, यह जानबूझकर, जानबूझकर और/या छलपूर्ण तरीकों से किया गया है। स्वाभाविक रूप से, दोनों समूहों में आने वाले मामलों के अलग-अलग परिणाम होते हैं और उनसे अलग तरीके से निपटा जाता है।

12. तथापि, धारा 11-ए, दोनों प्रकार के मामलों में पूर्वनिर्धारित रूप से निर्धारिती को कुछ नियमों और शर्तों के अधीन संशोधन करने की अनुमति देती है। ऐसे मामले जहां शुल्क का गैर-भुगतान या अल्प-भुगतान, आदि धोखाधड़ी, मिलीभगत आदि के कारण होता है, धारा 11-ए की उप-धारा (1-ए) के तहत निपटाए जाते हैं और ऐसे मामले जहां गैर-भुगतान या शुल्क का अल्प-भुगतान उप-धारा (2-बी) के तहत जानबूझकर नहीं किया जाता है।

13. धारा 11-ए की उप-धारा (2-बी) में यह प्रावधान है कि चूक करने वाला निर्धारिती, उस पर उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस जारी होने से पहले, अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी

द्वारा सुनिश्चित किए गए अवैतनिक शुल्क का भुगतान कर सकता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को उसके द्वारा किए गए भुगतान के बारे में लिखित रूप में सूचित कर सकता है और उस स्थिति में उसे उप-धारा (1) के तहत मांग नोटिस नहीं दिया जाएगा। लेकिन उप-धारा के स्पष्टीकरण 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के भुगतान को धारा 11-एबी के तहत प्रभार्य ब्याज से छूट नहीं होगी, यानी उस महीने के बाद की पहली तारीख से उस अवधि के लिए जिसमें शुल्क का भुगतान शुल्क के भुगतान की तारीख तक किया जाना चाहिए था।

14. उप-धारा (2-बी) के स्पष्टीकरण 2 में जो कहा गया है, उसे धारा 11-ए. बी. में दोहराया गया है कि जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है, वह व्यक्ति जिसने धारा 11-ए की उप-धारा (2-बी) के तहत शुल्क का भुगतान किया है, वह शुल्क के अलावा ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि चार धाराओं (11-ए, 11-ए. ए., 11-ए. बी. और 11-ए. सी.) की योजना के तहत, उन मामलों की श्रेणी

की ओर आकर्षित होने वाले जुर्माने के विपरीत, जिसमें शुल्क का भुगतान न करना या कम भुगतान करना आदि "धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को छिपाने या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन" के कारण होता है, किसी भी कारण से शुल्क के विलंबित या स्थगित भुगतान पर ब्याज लगाया जाता है। संशोधित मूल्यों के संतुलन की मांग करने वाले ग्राहकों को पूरक चालान जारी करते समय निर्धारिती द्वारा अंतर शुल्क का भुगतान स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2-बी) के प्रावधान के तहत आता है।

15. बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद बेंच ने सीसीई बनाम रुचा एंग में अपने फैसले में कहा। (पी) लिमिटेड, (2007 की पहली अपील संख्या 42 ने आई. डी. 1 पर निर्णय लिया) जिस पर न्यायाधिकरण ने राजस्व की अपील को खारिज करने के लिए भरोसा किया था, ने यह विचार रखा कि धारा 11-ए (2-बी) या धारा 11-ए. बी. का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा, जहां निर्धारिती द्वारा अंतर शुल्क का

भुगतान किया गया था, जैसे ही उसे पहले बेचे गए माल की कीमतों में वृद्धि के बारे में पता चला।

16. रुचा इंजीनियरिंग में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट है कि धारा 11-एबी तब लागू होती है जब भुगतान किया गया/लगाया गया शुल्क कम होता है। आयुक्त (अपील) और सी. ई. एस. टी. ए. टी. दोनों ने देखा है कि जब उनके ग्राहकों को संशोधित दरों के बारे में पता चला तो निर्धारिती ने तुरंत अपनी मर्जी से शुल्क का भुगतान किया। अंतर शुल्क उस समय देय था, अर्थात् जब पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू संशोधित दरों को निर्धारिती द्वारा सीखा गया था, जो माल की मंजूरी के बहुत बाद था और इसलिए, ब्याज के भुगतान का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि शुल्क का भुगतान उसी समय किया गया था जब यह पता चला कि यह देय था। यह पाते हुए कि धारा 11-ए (2) और 11-ए (2-बी) के प्रावधान लागू नहीं थे क्योंकि तत्काल मामले में स्थिति काफी अलग थी, धारा 11-एबी (1) बिल्कुल भी लागू नहीं थी, और इसलिए, निर्धारिती को ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। इसने आगे कहा कि इस तरह का मामला उस श्रेणी में नहीं



आएगा जहां उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था या कम भुगतान किया गया था।

17. हम रुचा इंजीनियरिंग में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्धारिती कीमतों के पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर अपने ग्राहकों से उच्च कीमतों के संतुलन की मांग करने में सक्षम था। इसलिए, यह इस प्रकार है कि बिक्री के समय माल का मूल्य अधिक था और उन्हें शुल्क के कम भुगतान पर जी से मुक्त कर दिया गया था। अंतर शुल्क का भुगतान बाद में ही किया गया जब निर्धारिती ने अपने ग्राहकों को शेष राशि की मांग करते हुए पूरक चालान जारी किए। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से शुल्क के अल्प-भुगतान का मामला था, हालांकि वास्तव में पूरी तरह से अनपेक्षित और छल आदि के किसी भी तत्व के बिना। इस प्रकार अंतर शुल्क का भुगतान स्पष्ट रूप से धारा 11-ए की उप-धारा (2-बी) के तहत किया गया और अधिनियम की धारा 11-ए. बी. के तहत ब्याज लगाया गया।"

14. इंटरनेशनल ऑटो लिमिटेड में भी लगभग ऐसी ही स्थिति थी। उस मामले में, निर्धारिती, अर्थात् इंटरनेशनल ऑटो लिमिटेड ने अपने

ग्राहकों (मोटर वाहनों के निर्माताओं) को वाहन के पुर्जों की आपूर्ति की थी, जो कच्चे माल की लागत, विनिर्माण लागत, लाभ मार्जिन आदि को ध्यान में रखते हुए वाहन के पुर्जों की कीमतें निर्धारित करते थे और निर्धारिती को आदेश देते थे। चूंकि हटाने की तारीख की कीमत और उस बढ़ी हुई कीमत के बीच मूल्य अंतर उत्पन्न हुआ जिस पर माल अंततः बेचा गया था, इसलिए विभाग ने अधिनियम की धारा 11-एबी के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए अंतर शुल्क पर ब्याज लगाने का प्रस्ताव करते हुए कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया। निर्धारिती ने बचाव पक्ष को उठाया कि खरीद आदेश में दर्शाई गई कीमतें अंतिम थीं और माल को हटाने के समय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं थीं और इस प्रकार, यह लघु शुल्क का मामला नहीं था जिस पर ब्याज लिया जा सकता था। एस. के. एफ. इंडिया लिमिटेड के निर्णय से व्यापक रूप से उद्धृत करने और उसी का पालन करने के बाद, निर्धारिती के उपरोक्त तर्क को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, फैसले में अधिनियम की धारा 11 एबी पर कुछ और चर्चा भी शामिल थी, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह निम्नानुसार चलता है:

"6. अधिनियम की धारा 11-ए शुल्क की वसूली से संबंधित है जो नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या अल्पकालिक या अल्पकालिक भुगतान किया गया है। उक्त धारा, जिसे 1978 के अधिनियम 25 द्वारा जोड़ा गया था, में एक बड़ा बदलाव आया जब संसद

ने 2001 के अधिनियम 14 (11-5-2001 से प्रभावी) और 2003 के अधिनियम 32 (14-5-2003 से प्रभावी) के माध्यम से उस धारा में बड़े बदलाव किए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि साथ ही 2001 के अधिनियम 14 ने अधिनियम की धारा 11-एबी में भी परिवर्तन किए।

7. एस. के. एफ. इंडिया लिमिटेड, (2009) 13 एस. सी. सी. 461 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित किया गया है, जैसा कि उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफों से देखा जा सकता है, कि धारा 11-ए की उप-धारा (2-8) में यह प्रावधान है कि चूक करने वाला निर्धारिती अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अवैतनिक शुल्क का भुगतान कर सकता है और उस 8 मामले में, चूक करने वाले ऐसे निर्धारिती को अधिनियम की धारा 11-ए. (1) के तहत मांग नोटिस नहीं दिया जाएगा। हालांकि, उप-धारा के स्पष्टीकरण 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के भुगतान को अधिनियम की धारा 11-ए 8 के तहत प्रभार्य ब्याज से छूट नहीं दी जाएगी। उप-धारा (2-8) के स्पष्टीकरण 2 में जो सी कहा गया है, उसे अधिनियम की धारा 11-ए 8 में दोहराया गया है, जो शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित है।

8. अधिनियम की धारा 11-ए (2-8) और धारा डी 11-ए 8 की योजना से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी हिसाब से राजस्व के नुकसान पर ब्याज लगाया जाता है। वर्तमान मामले में, एक तथ्य

निर्विवाद है, अर्थात्, मूल्य अंतर का संचय। अंतर मूल्य क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि मूल्य, जो कीमत का कार्य है, ई पर माल को हटाने/निकासी की तारीख सही नहीं थी। कि, यह कम बताया गया था। इसलिए, पूरक चालान द्वारा इंगित मूल्य एफ मंजूरी की तारीख को माल के मूल्य से सीधे संबंधित है, इसलिए, शुल्क में वृद्धि हुई है। यह बढ़ा हुआ शुल्क हटाने की तारीख को माल के सही मूल्य पर है। जब विभेदक शुल्क का भुगतान मंजूरी की तारीख के बाद किया जाता है, तो यह हटाने की तारीख को अल्प-भुगतान/अल्प-शुल्क का संकेत देता है, इसलिए, ब्याज जो जी राजस्व के नुकसान के लिए है, अधिनियम की धारा 11-ए8 के तहत देय हो जाता है।

9. हमारे विचार में, अधिनियम के तहत शुल्क की वसूली की योजना में पूरे बदलाव के साथ, विशेष रूप से 2001 के अधिनियम 14 और 2003 के अधिनियम 32 को शामिल करने के बाद, एम. आर. एफ. लिमिटेड में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा। वह निर्णय अधिनियम की धारा 11-बी की व्याख्या पर था, जो निर्धारिती द्वारा शुल्क की वापसी के दावे से संबंधित है। वह निर्णय 14-5-1983 पर अनुमोदित मूल्य सूची के संदर्भ में था। उस मामले में, निर्धारिती ने हटाने की तारीख की कीमत और कम कीमत जिस पर टायर बेचे गए थे, के बीच के अंतर पर उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा किया था। मूल्य को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। उस मामले में, निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि उसकी मूल्य सूची को

सरकार द्वारा 14-5-1983 पर अनुमोदित किया गया था, लेकिन उसके बाद, उपभोक्ता प्रतिरोध के कारण, भारत सरकार ने निर्धारिती को कीमतों को पूर्व-1>-1983 के स्तर पर वापस लाने का निर्देश दिया और उस कारण से, मूल्य अंतर उत्पन्न हुआ जिसके आधार पर निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क के रिफंड का दावा किया, जिसे इस अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि एक बार जब निर्धारिती ने वर्गीकरण पर माल को मंजूरी दे दी, तो निर्धारिती हटाने की तारीख को शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया और बाद में कीमतों में कमी को किसी भी कारण से विभाग के लिए चिंता का विषय नहीं बनाया जा सकता है, जहां तक उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की देयता का संबंध है। अधिनियम, 1944 की धारा में परिभाषा, लेकिन 2010 से पहले।"

10. वर्तमान मामले में, हम ब्याज के अधिरोपण से चिंतित हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राजस्व के नुकसान के लिए विभाग को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रभारित किया जाता है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम की धारा 11-ए की योजना में तब से काफी बदलाव आया है और परिस्थितियों में, हमारे विचार में, एम. आर. एफ. लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले का इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। हमारे विचार में, एस्केएफ इंडिया लिमिटेड में इस न्यायालय का निर्णय इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।"

15. श्री लक्ष्मीकुमारन, जो इन अपीलों में निर्धारिती की ओर से पेश हुए, ने एक अलग कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने दोतरफा रणनीति अपनाई। उनका पहला प्रयास यह दिखाना था कि एस्केएफ और इंटरनेशनल ऑटो के मामलों में निर्णय लागू नहीं थे क्योंकि उपरोक्त मामले अलग-अलग थे। उनका वैकल्पिक निवेदन था कि ये निर्णय अधिनियम की धारा 11एबी के प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं करते हैं और इसलिए, मामले को एक वृहद पीठ द्वारा नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। पहली प्रस्तुति को स्वीकार करना मुश्किल है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, जिस तथ्यात्मक परिदृश्य में उपरोक्त दो मामलों का निर्णय लिया गया था, वह लगभग समान था। जब इस न्यायालय ने समान प्रकार की घटनाओं के आधार पर अधिनियम की धारा 11एबी के प्रावधानों की एक विशेष तरीके से व्याख्या की और यह अभिनिर्धारित किया कि ब्याज किसी निश्चित शर्त पर देय नहीं था, तो निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि ये मामले तथ्यों के आधार पर अलग किए जा सकते हैं। इसलिए, हम श्री लक्ष्मीकुमारन की प्रस्तुतियों के दूसरे हिस्से का विज्ञापन करते हैं, जिसमें प्रासंगिक मामले के साथ वैधानिक प्रावधानों की पूरी लंबाई और चौड़ाई को शामिल करते हुए पूरी तीव्रता के साथ बहस की गई थी। पहले उदाहरण में, उन्होंने बताया कि इन अपीलों में दो अलग-अलग प्रकार के लेनदेन हो सकते हैं: (ए) जहां माल की कीमत हटाने के समय और स्थान पर 'तय' की जाती है, और

बाद की बातचीत के परिणामस्वरूप (अक्सर लंबी) खरीदार द्वारा कीमत को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जाता है; (बी) जहां हटाने के समय और स्थान पर कीमत 'तय नहीं' होती है (मूल्य वृद्धि खंड के अधीन), और अंतिम मूल्य पर विक्रेता और खरीदार के बीच बाद में सहमति होती है। उनके अनुसार पहली श्रेणी में आने वाले मामलों में अंतर शुल्क भी देय नहीं है। हालाँकि, ये सभी अपीलें दूसरी श्रेणी में आती हैं और इसलिए, हम पहली श्रेणी से संबंधित किसी भी चर्चा में शामिल नहीं हैं। हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि इन सभी अपीलों में, विवाद की अवधि (अर्थात् वह अवधि जिसमें मूल्य संशोधन के कारण पूरक चालान उठाए गए थे) 'लेनदेन मूल्य' की शुरुआत के बाद है। अधिनियम, 1944 की धारा में परिभाषा, लेकिन 2010 से पहले।

18. यह पक्षों का एक सामान्य मामला है और यहां तक कि निर्धारिती के लिए विद्वान वकील भी स्वीकार करते हैं कि गैर-निर्धारित मूल्य परिदृश्य में, मूल्य के बाद के संशोधन पर अंतर शुल्क का भुगतान किया जाना उत्तरदायी है, जिसे निर्धारिती ने पहले ही उस समय या उसके आसपास अंतर शुल्क का भुगतान कर दिया था जब विक्रेता और खरीदार द्वारा संशोधित मूल्य पर सहमति व्यक्त की गई थी। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या उस पर ब्याज माल की निकासी की तारीख से देय है, जब चालान के आधार पर शुल्क का भुगतान किया गया था, ग उस तारीख तक जब अंतर शुल्क का भुगतान किया गया था।

19. बुनियादी बातों से शुरू करते हुए, यह स्वयंसिद्ध है कि धारा 11 एबी के तहत ब्याज लगाया/लिया जा सकता है जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति में, ब्याज का भुगतान उस महीने की पहली तारीख से किया जाना चाहिए जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था। अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) में प्रावधान है कि माल का मूल्य माल के लिए 'वास्तव में भुगतान या देय' मूल्य होगा। इसका अर्थ है वह मूल्य जो ई को माल के खरीदार द्वारा 'भुगतान' या 'भुगतान करने के लिए सहमत' किया गया है। हम निर्धारिती के इस तर्क में बल पाते हैं कि धारा 11एबी में 'भुगतान किया जाना चाहिए था' अभिव्यक्ति को इस संदर्भ में समझना होगा। इस प्रकार, धारा 11 एबी के प्रयोजनों के लिए, 'भुगतान किया जाना चाहिए था' अभिव्यक्ति का अर्थ वह समय होगा जब विक्रेता और खरीदार द्वारा मूल्य पर सहमति हो। दूसरे शब्दों में, संशोधित मूल्य प्राप्त करने का विक्रेता का अधिकार केवल तभी स्पष्ट होता है जब खरीदार उसी प्रतिबंध के लिए सहमत होता है, और केवल उसी समय संशोधित मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने का दायित्व हो सकता है। दोनों पक्षों को उस समय अंतिम मूल्य के बारे में पता नहीं होता है जब माल हटाया जाता है। मंजूरी के बाद मूल्य संशोधन के संदर्भ में, खरीदार द्वारा संशोधित मूल्य की मंजूरी के बाद ही शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। मूल्य संशोधन के कारण अंतर शुल्क का



भुगतान उस महीने में किया जाता है जब विक्रेता (निर्धारिती) और खरीदार के बीच संशोधित मूल्य पर सहमति होती है और इसका भुगतान केवल उसी समय किया जाना चाहिए था न कि पहले।

20. 'भुगतान किए जाने वाले शुल्क की मात्रा क्या होनी चाहिए' और 'जब ऐसा शुल्क देय हो' के बीच के अंतर को भी ध्यान में रखना होगा। मूल्य संशोधन के मामलों में, शुल्क की मात्रा बढ़ी हुई कीमत पर होगी, लेकिन अंतर शुल्क के भुगतान का समय तब होता है जब पक्ष कीमतों में वृद्धि के लिए सहमत होते हैं। उस हिसाब पर, यह होगा कि अंतर शुल्क के लिए ब्याज घड़ी अंतर शुल्क देय होने की तारीख से टिक करना शुरू कर देगी, यानी बढ़ी हुई कीमतों के समझौते की तारीख और उससे पहले नहीं। इस अवधारणा को ब्याज के भुगतान के लिए 'प्रासंगिक तिथि' के संबंध में 2015 में धारा 11 ए में नवीनतम संशोधन के साथ स्पष्ट किया जाता है।

21. हम पहले ही एस. के. एफ. और ओ. इंटरनेशनल ऑटो में निर्णयों पर ध्यान दे चुके हैं, जिसमें वे कारण भी शामिल हैं जो इस विचार के समर्थन में दिए गए हैं कि ब्याज देय होगा। शुरुआत में, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि पीठ ने अधिनियम की धारा 11 एबी में आने वाली 'भुगतान किया जाना चाहिए था' अभिव्यक्ति के प्रभाव पर विचार नहीं किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिनियम की धारा 4 के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान 'लेनदेन मूल्य' पर किया जाना

है और इस तरह के लेनदेन मूल्य को माल की निकासी के समय देखा जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से, जब माल को मंजूरी दी गई थी, तो उत्पाद शुल्क का भुगतान उस कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया था जो वास्तव में ली गई थी और उक्त उद्देश्य के लिए उठाए गए चालान में दिखाई दिया था। विभाग यह दलील नहीं दे सकता कि उस तारीख तक यह कीमत नहीं ली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अंतर भुगतान बाद की तारीख में किया जाता है, तो मूल्य में उक्त अंतर के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क के लिए आगे की राशि देय हो जाती है। इसके अलावा, ऐसी घटना बाद की तारीख में हुई। जिस तारीख को माल को मंजूरी दी गई थी, उस तारीख तक इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि कीमतों में वृद्धि होगी और इस तरह की वृद्धि की सटीकता का पता लगाना समझ से परे था। भविष्य में मूल्य वृद्धि के आधार पर, माल की निकासी के समय, निर्धारिती से उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद करना असंभव होगा। इसलिए, जब उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था, तो मंजूरी की तारीख को इसे उक्त तारीख को 'अल्प भुगतान' के रूप में नहीं माना जा सकता था। परिणामस्वरूप जब मूल राशि, अर्थात् उत्पाद शुल्क स्वयं माल की निकासी की तारीख को देय (अर्थात् अंतर पर) नहीं था, तो ब्याज का भुगतान करने के लिए कानून का कोई सवाल नहीं हो सकता है।

22. निस्संदेह, अंतर मूल्य की प्राप्ति पर, जब खरीदार मूल्य में वृद्धि के लिए सहमत हो जाता है, तो आगे उत्पाद शुल्क भी देय हो जाता है और उस गणना पर यह कहा जा सकता है कि मूल रूप से भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क 'अल्प भुगतान' हो गया। हालांकि, यह केवल अंतर उत्पाद शुल्क पर भुगतान को आकर्षित करेगा, न कि उस पर ब्याज।

23. एस. के. एफ. इंडिया लिमिटेड और इंटरनेशनल ऑटो में दो निर्णय एक ही पीठ द्वारा दिए गए हैं। इंटरनेशनल ऑटो एसकेएफ इंडिया लिमिटेड का अनुसरण करता है। पीठ जिस प्राथमिक कारक से प्रभावित थी, वह यह था कि सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और इसलिए सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। यह इस आधार पर आगे बढ़ता है कि मूल रूप से माल को हटाने के समय जो कीमत बताई गई थी, वह 'कम बताई गई' थी (अंतर्राष्ट्रीय ऑटो का पैरा 8)। हालांकि, शुल्क के उद्देश्य से माल का मूल्य 'हटाने के समय' है, जैसा कि ऊपर जोर दिया गया है, जो मूल रूप से 1944 में अधिनियमित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की शुरुआत से मौलिक सिद्धांत बना हुआ है और आज तक वैध है। इसलिए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि उन वस्तुओं को हटाने की तारीख को कीमत 'कम' की गई थी।

24. हम आगे पाते हैं कि पीठ ने मामले में पहले के तीन सदस्यीय पीठ के फैसले को अलग किया: एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मद्रास के मामले में इस कथित आधार पर कि

अधिनियम की धारा 11 ए (जिसे मूल रूप से 1978 के अधिनियम 25 द्वारा जोड़ा गया था) में 'भारी परिवर्तन' हुआ था, जब संसद ने 2001 के अधिनियम 14 के माध्यम से उस धारा में बड़े बदलाव किए थे। 2003 का अधिनियम 32,2003 से लागू होगा। 14.05.2003 और 2001 का अधिनियम 14 जिसके तहत अधिनियम की धारा 11AB में भी संशोधन किया गया था। हालाँकि, हमारी राय है कि 2001 और 2003 में धारा 11 ए में किए गए संशोधनों का 'हटाने के समय की कीमत' के आधार पर माल के मूल्यांकन से कोई लेना-देना नहीं है। एम. आर. एफ. एक ऐसा मामला था जिसमें उक्त निर्धारिती द्वारा हटाने और उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की तारीख को खरीदार से एक विशेष मूल्य लिया जाता था। हालाँकि, इसके बाद सरकार के निर्देश पर इस कीमत को कम कर दिया गया। उस आधार पर, निर्धारिती ने हटाने की तारीख की कीमत और सरकार के निर्देश पर खरीदारों को बेचे गए कम मूल्य के बीच के अंतर पर उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए अपना दावा रखा। निर्धारिती के इस दावे को खारिज कर दिया गया और इस न्यायालय द्वारा आदेश को निम्नलिखित चर्चा के साथ बरकरार रखा गया: हमने निर्धारिती के विद्वान वकील को सुना है। एक बार जब निर्धारिती कारखाने के द्वार से माल को हटाने के समय उसके द्वारा बताए गए वर्गीकरण और मूल्य पर माल को मंजूरी दे देता है, तो निर्धारिती उस तारीख और समय पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है और बाद में उत्पाद शुल्क

विभाग में जहां तक हो सके, कमी कर देता है। उत्पाद शुल्क के भुगतान के दायित्व का संबंध था। यह वह दृष्टिकोण है जो न्यायाधिकरण द्वारा इंडो हैक्स लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. (1986) 25 ई. एल. टी. 69 (न्यायाधिकरण) के मामले में लिया गया था और हमें ऐसा लगता है कि न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण है कि शुल्क उस दर और मूल्य पर प्रभार्य है जब वस्तु को कारखाने के द्वार पर मंजूरी दी जाती है और बाद की तारीख में कम की गई कीमत पर नहीं। इसके अलावा जहां तक उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के दायित्व का संबंध है, ट्रिब्यूनल द्वारा उचित रूप से देखा गया है कि वस्तु की कीमतों में बाद में उतार-चढ़ाव की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है। इसलिए, भले ही हम यह मान लें कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा निर्मित टायरों की कीमत में वापसी केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के कारण हुई थी, कि अपने आप में, बिना कुछ और किए, अपीलकर्ता को मूल्य अंतर पर धनवापसी का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि सरकार के साथ इस संबंध में कुछ समझौता हुआ था और बाद वाला उत्पाद शुल्क को कम मूल्य की सीमा तक वापस करने के लिए सहमत हो गया था। ऐसा होने पर, हम निर्धारिती द्वारा की गई इस अपील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर देते हैं। इस प्रकार, हमारा विचार है कि एम. आर. एफ. लिमिटेड में निर्धारित सिद्धांत कायम रहेगा।

इसलिए, भले ही हम यह मान लें कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा

निर्मित टायरों की कीमत में वापसी केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के कारण हुई थी, कि अपने आप में, बिना कुछ और किए, अपीलकर्ता को मूल्य अंतर पर धनवापसी का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि सरकार के साथ इस संबंध में कुछ समझौता हुआ था और बाद वाला उत्पाद शुल्क को कम मूल्य की सीमा तक वापस करने के लिए सहमत हो गया था। ऐसा होने पर, हम निर्धारिती द्वारा की गई इस अपील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर देते हैं। इस प्रकार, हमारा विचार है कि एम. आर. एफ. लिमिटेड में निर्धारित सिद्धांत कायम रहेगा।

" ... इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाद के अवसर पर, न्यायालय संतुष्ट है कि उसका पहले का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था, तो उसे त्रुटि को सुधारने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि किसी पिछले निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत घोषित किया जाए, न्यायालय को अपने सदस्यों के बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति से संतुष्ट होना चाहिए कि उक्त दृष्टिकोण का संशोधन पूरी तरह से उचित है। यह संभव या वांछनीय नहीं है, और किसी भी मामले में ऐसे किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करना अनुचित होगा जो अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के प्रश्न से निपटने में न्यायालय के दृष्टिकोण को नियंत्रित करे। यह हमेशा कई प्रासंगिक विचारों पर निर्भर करेगा-उस दुर्बलता या त्रुटि की प्रकृति क्या है जिस पर पहले के दृष्टिकोण की समीक्षा

और संशोधन के लिए याचिका आधारित है? इससे पहले के अवसर पर, क्या प्रश्न के कुछ पेटेंट पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया था, या क्या न्यायालय का ध्यान किसी प्रासंगिक और भौतिक वैधानिक प्रावधान की ओर नहीं खींचा गया था, या क्या इस मुद्दे पर इस न्यायालय के किसी पिछले निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया था? क्या इस तरह की याचिका पर सुनवाई करने वाला न्यायालय काफी सर्वसम्मत है कि पहले के दृष्टिकोण में ऐसी त्रुटि है? इस त्रुटि का कानून के सामान्य प्रशासन या सार्वजनिक भलाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पहले के निर्णय का बाद के अवसरों पर इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया गया है? और, क्या पहले के निर्णय को वापस लेने से जनता को असुविधा, कठिनाई होगी? जब भी इस न्यायालय को अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, तो इन और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान से ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये विचार तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब पहले का निर्णय इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय होता है। हमने उपरोक्त विचार को ध्यान में रखा है और बी को लगता है कि एसकेएफ और ऑटो इंटरनेशनल में निर्णय के लिए हमारे द्वारा ऊपर दिए गए कारणों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। हम, इस प्रकार, रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि इस मामले में शामिल मुद्दे पर गौर करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन करने के

लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए,  
जो दूरगामी प्रभाव वाले मौलिक महत्व का है।

निधि जैन

मामले को वृहद पीठ को भेजा गया।



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सुनील कुमार की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।